

# आयुक्त(अपील)का कार्यालय, Office of the Commissioner (Appeal),

केंद्रीय जीएसटी, अपील आयुक्तालय,अहमदाबाद Central GST, Appeal Commissionerate, Ahmedabad जीएसटी भवन, राजस्वमार्ग, अम्बावाड़ीअहमदाबाद३८००१५. CGST Bhavan, Revenue Marg, Ambawadi, Ahmedabad 380015 207926305065 – टेलेफैक्स07926305136



<u>DIN</u>: 20230164SW000032323B

स्पीड पोस्ट

क फाइल संख्या : File No : GAPPL/COM/STD/219/2022 /6867 - ने \

ख अपील आदेश संख्या Order-In-Appeal No. AHM-EXCUS-001-APP-119/2022-23 दिनाँक Date: 02-01-2023 जारी करने की तारीख Date of Issue: 04.01.2023

आयुक्त (अपील) द्वारापारित Passed by **Shri Akhilesh Kumar**, Commissioner (Appeals)

- ग Arising out of OIO No. CGST-VI/Dem-22/Roopesh Bhatia/AC/DAP/21-22 दिनाँक: 23.03.2022 passed by Assistant Commissioner, CGST, Division VI, Ahmedabad South
- ध अपीलकर्ता का नाम एवं पता Name & Address

### **Appellant**

 The Assistant Commissioner CGST, Division VI, Ahmedabad South 3<sup>rd</sup> Floor, APM Mall, Nr. Seema Hall, Anandnagar Road, Satellite, Ahmedabad

#### Respondent

M/s Roopesh Bhogilal Bhatia
 314, Super Mall, C.G. Road, Ahmedabad - 380009

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-In-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way:

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन

## Revision application to Government of India:

- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप—धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001 को की जानी चाहिए।
- (i) A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4<sup>th</sup> Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid:
- (ii) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानिकार खाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।
- (ii) In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

1

- (क) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलें में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।
- (A) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
- (ख) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।
- (B) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो डयूटी केडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

- (c) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए—8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनाँक से तीन मास के भीतरमूल—आदेश एवं अपील आदेश की दो—दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ.का मुख्य शीर्ष के अंतर्गत धारा 35—इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर—6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम होतो रूपये 200/—फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्नरकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/— की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35—बी/35—इ के अंतर्गत:— Under Section 35B/35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-
- (क) उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलों के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण<u>(सिस्टेट)</u> की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में 2<sup>nd</sup> माला, बहुमाली भवन , असरवा , गिरधरनागर, अहमदाबाद—380004
- (a) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at 2<sup>nd</sup> Floor, Bahumali Bhawan, Asarwa, Girdhar Nagar, Ahmedabad : 380004. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.

(3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल ओदश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होत हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थित अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता हैं।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

(4) न्यायालय शुल्कअधिनियम 1970 यथासंशोधित की अनुसूचि—1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूलआदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रतिपर रू.6.50 पैसे कान्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-litem of the court fee Act, 1975 as amended.

(5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

2ण सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण<u>(सिस्टेट)</u>,के प्रतिअपीलो के मामले में कर्तव्यमांग(Demand) एवं दंड(Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है।(Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के अंतर्गत, शामिल होगा "कर्तव्य की मांग"(Duty Demanded)-

a. (Section) खंड 11D के तहत निर्धारित राशि;

इण लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशि;

बण सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि.

⇒ यह पूर्व जमा 'लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना में, अपील' दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया
है.

For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited, provided that the pre-deposit amount shall not exceed Rs.10 Crores. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

(cclvi) amount determined under Section 11 D;

(cclvii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;

(cclviii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% -भुग्रातान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती हैं।

view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where benalty alone is in dispute."

<u>?</u>.

### ORDER-IN-APPEAL

The present appeal has been filed by the Assistant Commissioner, CGST, Division-VI, Commissionerate Ahmedabad South (hereinafter referred to as the "appellant"), on the basis of Review Order No. 25/2022-23 dated 07.07.2022 passed by the Principal Commissioner, Central GST, Ahmedabad South Commissionerate in terms of Section 84 (1) of the Finance Act, 1994, against Order in Original No. CGST-VI/Dem-22/Roopesh Bhatia/AC/DAP/21-22 dated 23.03.2022 [hereinafter referred to as "impugned order"] passed by the Assistant Commissioner, CGST, Division-VI, Commissionerate Ahmedabad South [hereinafter referred to as "adjudicating authority"] in the case of M/s. Roopesh Bhogilal Bhatia, 314, Super Mall, C.G. Road, Ahmedabad – 380009 [hereinafter referred to as the respondent].

- 2. Briefly stated, the facts of the case are that a difference in the income as shown in the ITR filed by the respondent for F.Y. 2015-16 and the income shown by them in their ST-3 return amounting to Rs.26,79,087/- was noticed. Therefore, the respondent was issued Show Cause Notice bearing No. V/WS06/O&A/SCN-314/2020-21 dated 26.12.2020 wherein it was proposed to:
  - A. Demand and recover the service tax amounting to Rs.4,01,863/- under the proviso to Section 73 (1) of the Finance Act, 1994 along with interest under Section 75 of the Finance Act, 1994.
  - B. Impose penalty under Sections 77(1)(c), 77 (2) and 78 of the Finance Act, 1994.
- 3. The SCN was adjudicated vide the impugned order and the proceedings initiated against the respondent were dropped.
- 4. Being aggrieved with the impugned order, the appellant department have filed the present appeal on the following grounds:



- i. The adjudicating authority has erred in dropping the demand of service tax without recording any proper and clear findings as to how on the basis of the ledger and invoices, it is evident that the respondent had provided services of Construction, Erection, Commissioning of original works of a single residential unit other than as a part of residential complex.
- ii. From the findings at Para 15 of the impugned order, it is evident that the adjudicating authority has failed to give clear findings and has casually passed the order giving undue benefit to the respondent. The impugned order gives an impression that the same has been passed in an arbitrary manner without application of mind.
- 5. The respondent have vide their letter dated 09.12.2022 filed their cross-objection to the appeal, wherein it was contended that:
  - > They are engaged in providing Electrical Work Contract services to commercial as well as residential customers and are registered with the service tax department.
  - ➤ They had submitted the requisite documents or details in their reply to the SCN which proves that service tax liability does not arise on the differential amount derived from Form 26AS.
  - ➤ They had also submitted the statement of reconciliation between their ST-3 returns and Form 26AS. They had also provided copies of invoices raised by them for carrying out electrical fitting work. After considering the documents submitted by them, the demand of service tax was dropped.
  - > The appeal filed by the department has not specified the exact reason as to how the adjudicating authority has not given any proper reasoning in dropping the demand.
  - > The findings as Para 15 regarding non-applicability of service tax registration is a mistake on the part of the adjudicating authority as can be seen from Para 1 of the impugned order wherein it is clearly mentioned that they are registered with the service tax department.

They submit copies of the invoices issued by them to their customers, along with layout plan.

6

- 6. Personal Hearing in the case was held on 21.12.2022. Ms. Bhagyashree Dave and Ms. Foram Dhruv, Chartered Accountants, appeared on behalf of the respondent for the hearing. They reiterated the submissions made in the cross-objection dated 09.12.2022.
- 7. I have gone through the facts of the case, submissions made in the Appeal Memorandum, the cross-objections filed by the respondent and the material available on records. The issue before me for decision is whether the impugned order dropping the demand of service tax amounting to Rs.4,01,863/-, in the facts and circumstances of the case, is legal and proper or otherwise. The demand pertains to F.Y. 2015-16.
- 8. I find that the respondent was issued SCN on the basis of the data received from the Income Tax Department and the respondent was called upon to submit documents/details in respect of the difference found in their income reported in the ST-3 returns as compared to the Form 26AS. However, the respondent failed to submit the same. Therefore, the respondent was issued SCN demanding service tax on the differential income by considering the same as income earned from providing taxable services. However, no cogent reason or justification is forthcoming for raising the demand against the respondent. It is also not specified as to under which category of service, the non payment of service tax is alleged against the respondent. The demand of service tax has been raised merely on the basis of the data received from the Income Tax. However, the data received from the Income Tax department cannot form the sole ground for raising of demand of service tax.
- 8.1. I find it pertinent to refer to Instruction dated 26.10.2021 issued by the CBIC, wherein it was directed that:

"It was further reiterated that demand notices may not be issued indiscriminately based on the difference between the ITR-TDS taxable value and the taxable value in Service Tax Returns.

3. It is once again reiterated that instructions of the Board to issue show cause notices based on the difference in ITR-TDS data and service tax returns only after proper verification of facts, may be followed diligently. Pr. Chief Commissioner/Chief Commissioner(s) may devise a suitable mechanism to

monitor and prevent issue of indiscriminate show cause notices. Needless to mention that in all such cases where the notices have already been issued, adjudicating authorities are expected to pass a judicious order after proper appreciation of facts and submission of the noticee."

- 8.2 However, in the instant case, I find that no such exercise, as instructed by the Board has been undertaken, and the SCN has been issued only on the basis of the data received from the Income Tax department. Therefore, on this very ground the demand raised vide the impugned SCN is liable to be dropped.
- Coming to the merits of the case, it is observed that the adjudicating 9. authority has clearly mentioned at Para 7 and 11 of the impugned order that he has gone through the Profit and Loss Account of F.Y. 2015-16 and Ledger of Income and invoices. After examining these documents, the adjudicating authority has concluded that the activity carried out by the respondent is covered by Entry No. 14 (b) of Notification No.25/2012-ST dated 20.06.2012 and, therefore, held that service tax is not leviable. Accordingly, the adjudicating authority has dropped the proceedings against the respondent. The respondent have submitted copies of the invoices issued by them as part of their cross-objection. I have perused the same and find that there is no infirmity in the finding of the adjudicating authority that the amounts received by the respondent are towards services pertaining to a single residential unit otherwise than as a part of a residential complex and, accordingly, exempted in terms of the said Notification.
- 9.1 It is further observed that the adjudicating authority has at Para 12 of the impugned order, tabulated the revised service tax liability of the respondent wherein he has reconciled the taxable value of services provided by the respondent as compared to the income shown in their ITR and concluded that there was no difference in the taxable value of services apart from the income which is exempted in terms of Entry No.14 (b) of Notification No.25/2012-ST dated 20.06.2012. Accordingly, the adjudicating authority has held that the respondent was not liable to pay service tax

emanded in the SCN issued to them.

8

- 10. It is observed that the appellant department has not brought on record any document or evidence indicating that the conclusions arrived at by the adjudicating authority, after verification of the documents submitted by the respondent, are erroneous. Neither has the appellant department refuted or countered any of the findings of the adjudicating authority. Consequently, I am of the considered view that the appeal filed by the appellant department is devoid of merits.
- 11. In view of the facts discussed hereinabove, I uphold the impugned order and reject the appeal filed by the appellant department.
- 12. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

The appeal filed by the appellant department stands disposed of in

above terms.

(Akhilesh Kumar) Commissioner (Appeals)

Date: 02.01.2023.

Attested:

(N.Suryanarayanan. Iyer) Superintendent(Appeals), CGST, Ahmedabad.

### BY RPAD / SPEED POST

To

The Assistant Commissioner, CGST, Division- VI.

Commissionerate: Ahmedabad South.

M/s. Roopesh Bhogilal Bhatia, 314, Super Mall, C.G. Road, Ahmedabad – 380009

Appellant

Respondent

### Copy to:

- 1. The Chief Commissioner, Central GST, Ahmedabad Zone.
- 2. The Principal Commissioner, CGST, Ahmedabad South.
- 3. The Assistant Commissioner (HQ System), CGST, Ahmedabad South. (for uploading the OIA)

Guard File.

5. P.A. File.